Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 19-08-25

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 19 Aug, 2025

Edition: International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 2 : International Relations	सीमा पर तनाव कम करने की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए: जयशंकर ने वांग से कहा
Page 06 Syllabus : GS 3 : Indian Economy	जुलाई में बेरोज़गारी दर घटकर 5.2% हुई: सरकारी सर्वेक्षण
Page 07 Syllabus : GS 3 : Science and Technology	सरकार की इथेनॉल मिश्रण योजना के बारे में विज्ञान क्या कहता है?
Page 08 Syllabus : GS 2 : International Relations	अलास्का की हवाएँ, भारत और ट्रम्प-पुतिन शिखर सम्मेलन
Page 09 Syllabus : GS 1 : Indian Society	महिलाओं का सच्चा सशक्तिकरण क्या है
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus : GS 2 : International Relation	वैश्विक भुखमरी को समाप्त करने का मार्ग भारत से होकर गुजरता है

Page 01 : GS 2 : International Relations

विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, जो द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन यात्रा से पहले हुई है। कज़ान 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद यह पहली मंत्रिस्तरीय वार्ता है।

De-escalation process on border must move forward: Jaishankar to Wang

Suhasini Haidar
NEW DELHI

The process of withdrawing troops from the Line of Actual Control needs to "move forward", External Affairs Minister S. Jaishankar told Chinese Foreign Minister Wang Yi, as the two sides began discussions to improve bilateral and trade relations in Delhi on Monday.

They also prepared for Prime Minister Narendra Modi's visit to China for the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit at the end of the month. On Tuesday, Mr. Wang will meet National Security Advisor Ajit Doval for the 24th round of Special Representative talks that focuses on the resolution of the boundary dispute between India and China.

In a special gesture, Mr. Modi is also expected to meet Mr. Wang on Tuesday, ahead of his meetings with Chinese President Xi Jinping, at the SCO summit in Tianjin. "Having seen a difficult period in our relationship... our two nations now seek to move ahead," Mr. Jaishankar said in his opening remarks as the two sides met at the official venue, Hyderabad House. "The basis for any positive momentum in our ties is the ability to jointly maintain peace and tranquillity in border areas."

"It is also essential that the de-escalation process move forward," he added, drawing attention to the fact that demobilisation at the LAC and dismantling of infrastructure, to return to the status quo before April 2020, have not been completed 10 months after the leaders met, although other parts of the relationship have been restored.

According to a statement issued by the Chinese Ministry of Foreign Affairs, Mr. Wang pointed to global challenges, including "unilateral bullying" in "free trade and the international order", a reference to the U.S. trade tariffs. He said that China was prepared to work with India and other neighbours to establish five aspects of "peace, tranquillity, prosperity, beauty and friendship". "Both sides should carefully draw on the lessons learned over the past 75 years... view each other as partners," Mr. Wang added.

Mr. Modi and the Chinese President last met in October 2024 in Kazan and agreed to normalise ties after a four-year military stand-off at the LAC. Mr. Wang's visit is the first such ministerial visit since the Kazan meeting, and part of a number of exchanges to restore ties between the two countries. In June this year, China and India resumed the Kailash Mansarovar Yatra for pilgrims, and India has resumed issuing tourist visas for Chinese tourists. Both sides are also discussing the resumption of sharing river water data, as well as starting direct flights between India and China, which have been suspended since 2020.

Building ties: External Affairs Minister S. Jaishankar welcomes Chinese Foreign Minister Wang Yi, in New Delhi on Monday, as the two sides began discussions to improve bilateral relations. ANI

प्रमुख घटनाक्रम

1. सीमा मुद्दा (एलएसी पर तनाव कम करना)

- o जयशंकर ने ज़ोर देकर कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए।
- o समझौतों के बावजूद, सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे को हटाना (अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल करने के लिए) अभी भी अधूरा है।
- o भारत समग्र संबंधों की प्रगति को सीमा पर शांति और स्थिरता से जोड़ता है।

2. चीन का रुख

- o वांग यी ने व्यापार में "एकतरफा दादागिरी" (अमेरिका का संदर्भ) जैसी वैश्विक चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
- o पड़ोसियों के साथ संबंधों में शांति, समृद्धि, सुंदरता, शांति और मित्रता का एक ढाँचा पेश किया।
- o दोनों पक्षों से "75 वर्षों के संबंधों" से सीखने और साझेदार के रूप में कार्य करने का आह्वान किया।

3. द्विपक्षीय विश्वास-निर्माण उपाय (सीबीएम)

o कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली।

o चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा बहाल।

o नदी जल डेटा साझाकरण और सीधी उड़ानों पर वार्ता (2020 से स्थगित)।

4. सामरिक महत्व

o यह बैठक एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है—जो क्षेत्रीय सुरक्षा और संपर्क सहयोग का मंच है।

o इसे 4 साल के सीमा गतिरोध के बाद कज़ान के बाद संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।

व्यापक महत्व

- भारत का रुख: संबंधों का कोई भी सामान्यीकरण सीमा तनाव के समाधान पर निर्भर है (गलवान 2020 के बाद से भारत के रुख में स्पष्ट निरंतरता)।
- चीन का रुख: सीमा तनाव को व्यापक सहयोग (आर्थिक, व्यापार, बहुपक्षीय मुद्दों) से अलग करने का इच्छुक।

भू-राजनीतिक संदर्भ:

o दोनों देश आर्थिक मंदी और अमेरिका के नेतृत्व वाले ब्लॉक के दबाव का सामना कर रहे हैं।

o एससीओ और ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय मंच दोनों के लिए बहुध्रुवीयता को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारत के लिए निहितार्थ

1. सुरक्षा

o सीमा मुद्दा अभी भी अधूरा है, अगर तनाव कम करने में देरी होती है तो तनाव बढ़ने का खतरा है।

2. कूटनीति

o आर्थिक और बहुपक्षीय संबंधों में संप्रभुता पर दृढ़ता और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

3. अर्थव्यवस्था

- तनाव के बावजूद, चीन एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। सीमित आदान-प्रदान बहाल करने से व्यापार प्रवाह आसान हो सकता है।

4. क्षेत्रीय संतुलन

- भारत को चीन और अमेरिका के साथ संबंधों को एक साथ आगे बढ़ाना चाहिए, बिना किसी के खिलाफ़ दिखे।

आगे की राह

- मज़बूत संबंध: इस बात पर ज़ोर देते रहें कि सीमा पर शांति = संबंधों में प्रगति।
- विश्वास निर्माण: अविश्वास कम करने के लिए लोगों के बीच संबंधों, पर्यटन, नदी सहयोग और उड़ानों का विस्तार करें।
- सामरिक स्वायत्तता: संप्रभुता की रक्षा करते हुए, अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता में शामिल होने से बचें।
- बहुपक्षीय कूटनीति: नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए SCO/BRICS जैसे मंचों का उपयोग करें।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: सीमा पर शांति भारत-चीन संबंधों की नींव है। हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। **(150 Words)**

Page 06:GS 3 : Indian Economy

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, भारत की बेरोजगारी दर जून 2025 के 5.6% से घटकर जुलाई 2025 में 5.2% हो जाएगी। इसके साथ ही महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में वृद्धि और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में सुधार भी हुआ है। हालाँकि ये आँकड़े सकारात्मक रुझान दर्शाते हैं, लेकिन गहन विश्लेषण से भारत के श्रम बाजार में लगातार बनी हुई संरचनात्मक चुनौतियों का पता चलता है।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष

1. बेरोजगारी दर (यूआर)

- o कुल: 5.2% (जून में 5.6% से कम)।
- o ग्रामीण: 4.4%, शहरी: 7.2%।
- o महिलाएँ: ग्रामीण 3.9%, शहरी 8.7%; पुरुष: ग्रामीण 4.6%, शहरी 6.6%।

2. श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)

- o कुल: 41.4%।
- o महिलाएँ: 25.5% (24.5% से ऊपर)।
- o पुरुष: 57.4%।
- o ग्रामीण पुरुष: 78.1%, ग्रामीण महिलाएँ: 36.9%; शहरी पुरुष: 75.1%, शहरी महिलाएँ: 25.8%।

3. श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)

- o राष्ट्रीय: 52% (51.2% से ऊपर)।
- o ग्रामीण: 54.4%, शहरी: 47%।

Unemployment rate declines to 5.2% in July: govt. survey

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The rate of unemployment in the country declined to 5.2% in July from 5.6% in June, shows the Periodic Labour Force Survey released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation on Monday.

The Labour Force Participation Rate (LFPR) for women showed a marginal increase to 25.5% in July from 24.5% in June. The LFPR for men stood at 57.4%, while for all persons, it was 41.4%.

The LFPR for men aged 15 and above in rural areas was 78.1% and for women, it was 36.9%. "In urban areas, the LFPR among females of age 15 years and above during July was 25.8% compared with 75.1% observed for males of the same age group," the survey noted.

The number of persons covered by the survey was 3,79,222 (2,16,832 in rural areas and 1,62,390 in urban areas). FILE PHOTO

The unemployment rate (UR) for persons aged 15 and above stood at 5.2%. In rural areas, it was 4.4% and 7.2% in urban areas. For women in rural areas, the UR was 3.9%. For men, it was 4.6%. For women in urban areas, the UR was was 8.7% compared with 6.6% among men.

The Worker Population Ratio (WPR), which defines the proportion of those who are employed among the total population, in rural areas for persons aged 15 and above was 54.4%. In June it was 53.3%. The WPR in urban areas was 47% and at the national level, it was 52%, 0.8 percentile points higher than June.

The Labour Bureau surveyed 89,505 (49,355 in rural areas and 40,150 in urban areas) households and the number of persons surveyed was 3,79,222 (2,16,832 in rural areas and 1,62,390 in urban areas).

विश्लेषण और निहितार्थ

- **सकारात्मक रुझान:**
  - o बेरोज़गारी दर में गिरावट, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, रोज़गार अवशोषण में सुधार का संकेत देती है।
  - o महिलाओं की बढ़ती LFPR महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में एक क्रमिक लेकिन उत्साहजनक बदलाव का संकेत देती है।
  - o WPR में वृद्धि, अधिक लोगों के उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होने का संकेत देती है।

- **लगातार चुनौतियाँ:**
  - o शहरी बेरोज़गारी दर उच्च बनी हुई है, खासकर महिलाओं के लिए (8.7%), जो सीमित औपचारिक नौकरियों, सुरक्षा संबंधी मुद्दों और लचीले कार्य विकल्पों की कमी जैसी संरचनात्मक बाधाओं को दर्शाती है।
  - o लैंगिक अंतर अभी भी व्यापक है: पुरुषों का एलएफपीआर (57.4%) महिलाओं (25.5%) की तुलना में दोगुने से भी अधिक है।
  - o रोज़गार की गुणवत्ता का आकलन नहीं किया गया: कई नई नौकरियाँ कम वेतन वाले अनौपचारिक क्षेत्रों या अल्प-रोज़गार में हो सकती हैं।
  - o ग्रामीण एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर में सुधार आंशिक रूप से उत्पादक अवसरों के बजाय संकट-प्रेरित रोज़गार को दर्शा सकते हैं।

- **नीतिगत प्रासंगिकता:**
  - o शहरी रोज़गार सृजन की आवश्यकता को दर्शाता है, विशेष रूप से विनिर्माण और सेवाओं में।
  - o महिला-केंद्रित श्रम नीतियों (कौशल प्रशिक्षण, बाल देखभाल सुविधाएँ, सुरक्षा, लचीली नौकरियाँ) की आवश्यकता।
  - o मुख्य बेरोज़गारी दर से परे अल्प-रोज़गार और अनौपचारिकता पर नज़र रखने का महत्व।

निष्कर्ष

- जुलाई 2025 तक भारत की बेरोज़गारी दर का घटकर 5.2% रह जाना अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्साहजनक संकेत है, जो श्रम बाजार में क्रमिक सुधार को दर्शाता है। हालाँकि, लगातार बना हुआ शहरी-ग्रामीण विभाजन, लैंगिक असमानताएँ और रोज़गार की गुणवत्ता को लेकर चिंताएँ इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि भारत की रोज़गार चुनौती चक्रीय से ज़्यादा संरचनात्मक है। सतत विकास के लिए, भारत को गुणवत्तापूर्ण रोज़गार सृजन, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और शहरी रोज़गार की कमज़ोरियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, और श्रम सुधारों को समावेशी विकास के व्यापक दृष्टिकोण के साथ जोड़ना होगा।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: पीएलएफएस जुलाई 2025 में रिपोर्ट किए गए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) के संदर्भ में**,** निम्नलिखित में से कौन सा सही है**?**

(A) डब्ल्यूपीआर को कुल जनसंख्या में श्रम शक्ति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

(B) ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूपीआर शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक था।

(C) जून 2025 की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूपीआर में गिरावट आई है।

(D) डब्ल्यूपीआर कार्यशील आयु वर्ग की आबादी में बेरोजगारी को मापता है।

उत्तर: **B**)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: हालिया पीएलएफएस आँकड़े बेरोज़गारी में गिरावट दर्शाते हैं**,** लेकिन भारत के श्रम बाजार में संरचनात्मक चुनौतियों को भी उजागर करते हैं। चर्चा कीजिए। **(150 Words)**

Page : 07 :GS 3 : Science and Technology

भारत का इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य 2025 तक 20% इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण (E20) करना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना है। इथेनॉल, जो गन्ना, खाद्यान्न या लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास से प्राप्त एक जैव ईंधन है, को एक स्वच्छ और स्वदेशी विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि, इसे अपनाने से वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक आधार पर, विशेष रूप से दक्षता, वाहन अनुकूलता और दीर्घकालिक स्थिरता के संबंध में, प्रश्न उठते हैं।

वैज्ञानिक और तकनीकी पहलू

1. उत्पादन स्रोत

- o गुड़ (C-भारी, B-भारी), गन्ने के रस, टूटे चावल, मक्का या लिग्नोसेल्यूलोसिक अपशिष्ट से प्राप्त।
- o किण्वन इनवर्टेज और ज़ाइमेज़ जैसे एंजाइमों का उपयोग करके शर्करा को इथेनॉल में परिवर्तित करता है।

2. ईंधन गुण

- o कैलोरी मान: पेट्रोल से कम → संभावित रूप से माइलेज कम करता है।
- o ऑक्टेन संख्या: उच्च → एंटी-नॉकिंग गुणों और दहन दक्षता में सुधार करता है।
- o आर्द्रताग्राही प्रकृति: पानी सोख लेता है → ईंधन प्रणालियों में जंग लगने, अवरोध और अवरोध का जोखिम।

3. वाहनों पर प्रभाव

- oआधुनिक BS-VI वाहन (इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाइयों के साथ) दहन मापदंडों को

The government procures ethanol either from sugarcane-based raw materials like C-heavy molasses, B-heavy molasses, sugarcane juice, sugar, or sugar syrup, or damaged food grains like broken rice, maize, or cellulosic and lignocellulosic materials. KARTHIKEYAN G.

What does science say about the govt.'s ethanol blending plan?

The ethanol push echoes past global experiments. Unlike the most celebrated example, Brazil, which began decades ago in an studied manner, India's more rapid move towards blending has left drivers grappling with practical issues of mileage, corrosion, and higher service costs

Priyali Prakash

In 2021, the Government of India said it will move to 20% ethanol blending in petrol by 2025 with the two-pronged goal of cutting carbon emissions and reducing the country's dependence on foreign oil.

While vehicles modified to be compatible with the new composition started rolling out in April 2025, the government's push for 20% ethanol-blended petrol (E20) has left vehicle-owners worried about the impact on their older vehicles and about a surge in maintenance costs.

Ethanol, or ethyl alcohol, is a biofuel: it is made from plant waste called biomass. Regular petrol is a hydrocarbon made from the fossilised remains of organic matter buried for millions of years.

When mixed with a fossil fuel like petrol, ethanol acts as an oxygenate that helps the petrol burn better.

Making ethanol

Under India's ethanol-blending programme, the government procures ethanol either from sugarcane-based raw materials like C-heavy molasses, B-heavy molasses, sugarcane juice, sugar, or sugar syrup, or damaged food grains like broken rice, maize, or cellulosic and lignocellulosic materials.

Molasses is a byproduct of sugarcane production. It is a thick, dark syrup about 40% rich in sugars that can be fermented but which can't be extracted further.

C-heavy molasses is the final byproduct of the sugar production process, with molasses content around 28-32%. B-heavy molasses is an intermediate byproduct of the same process and has a higher molasses content, ranging from 48% to 52%.

Ethanol is made from molasses by fermentation – using yeast enzymes to catalyse the breakdown of sugar molecules in the presence of water. An everyday example of fermentation is ginger soda. If you put ginger, sugar, and water in an airtight container for a few days, it becomes fizzy.

This is because the microbes in ginger feed on the sugar, releasing carbon dioxide, which makes carbonic acid with water.

In the first step of ethanol production from molasses, sucrose molecules in the syrup are diluted with water. Then they break down into glucose molecules in the presence of invertase.

These glucose molecules further react in the presence of zymase to form ethanol and release carbon dioxide.

Producing ethanol from food grains and lignocellulosic materials also involves other processes that break them down to fermentable sugars first. Lignocellulosic biomass is plant matter with a high carbohydrate content and is usually composed of parts not used for food or feed. This biomass is rich in cellulose, hemicellulose, and lignin.

Chemical nature, energy efficiency

Two factors are key to understanding ethanol's energy efficiency: the calorific value and the octane number.

The calorific value of a fuel denotes its yield: a higher calorific value means more energy. The calorific value of ethanol is significantly lower than that of petrol, so the fuel's overall burning efficiency should theoretically decrease. However, the government has maintained that the drop in fuel performance is not significant and that it is governed by a mix of other factors, including "driving habits, maintenance practices such as oil changes and air filter cleanliness, tyre pressure and alignment, and even air conditioning load."

The octane number is a measure of a fuel's resistance to engine knocking or burning prematurely. Ethanol has a higher octane number than petrol. Thus, it has the potential to reduce the knock resistance significantly. However, because of its lower energy content, the amount of energy the engine can extract per litre of blended fuel decreases with increasing ethanol content.

This said, the drop in mileage drivers have raised concerns about won't be significant, Sudheer Kumar Kuppili, a research fellow at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, said.

"The compensation for having lower energy would be quite low when you are moving from E10 to E20," Kuppili said. "It would be significant only when we shift to 100% ethanol. Most of the uproar these days about the reduction in vehicular mileage is fuelled by many factors, which are difficult to assess."

In fact, experts said the thing to focus on here is ethanol's hygroscopic nature. That is, ethanol has a considerable tendency to attract and attach water molecules to itself. This in turn affects the vehicle's components and fuel performance in new ways.

Independent expert Noble Varghese said the main concern is the increased possibility of corrosion.

"Ethanol affects the rubber components of a fuel system, which are mainly the piping, the fuel tank, the injectors, the filters, and the combustion chambers. The combustion chamber and the engine block itself are not as affected by ethanol, but what is affected is the fuel tank, the rubber piping, and the injector," Varghese said.

"Ethanol tends to attract water, so if the vehicle is not used everyday, water tends to collect in the fuel tank, which is corrosive for the tank. This causes another problem too: rust particles mix with fuel and go into the fuel line and clog it," he added.

"That in itself will reduce the mileage. This is not primarily because of ethanol's thermodynamic properties but more because of the components, which are not suited to E20 fuel."

> When the blending happens, it alters the stoichiometric ratio, i.e., air-to-fuel ratio, which in turn affects the speed of combustion and heat release
>
> SUDHEER KUMAR KUPPILI
> LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL MEDICINE

The government has, however, maintained that replacing older rubber parts and gaskets designed for the non-blended fuel is "inexpensive and can be easily managed during routine servicing."

A statement released by the Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG) on August 12 also said this change would be required only "once in the lifetime of the vehicle" and at "any authorised workshop."

Kuppili also said moisture won't be a significant problem.

"This might be a problem for older vehicles, which are probably already worn out. This should not be a problem for BS-IV or BS-VI vehicles. The fuel's hygroscopic nature might have a noticeable effect when you are in colder parts of the country. However, in those regions, fuels are usually mixed with additives to avoid freezing," he explained.

"Also, when you are using a vehicle regularly, any moisture that accumulates will be evaporated by the high engine temperatures (>400° C)," he said.

Kuppili wished to clarify that he hasn't worked on this particular issue of the fuels.

Comparisons with Brazil

Comparing the Indian ethanol-blending story with that of Brazil may not be justified, as the South American country currently uses E27 petrol as well and paced this upgrade out over decades.

Brazil first decided to lower its dependence on imported petrol in 1975 with its Proálcool programme during the oil crisis in the 1970s. Over the next few years, it focused on building capacity by working with researchers, expanding the production of ethanol from sugarcane with the specific purpose of mixing it with petrol, providing subsidies, incentives, and tax breaks to reduce the costs of production, and increasing the competitiveness of ethanol.

The country also has a large market for vehicles fit with flex-fuel engines that allow vehicles to readily adapt to petrol with different ethanol fractions.

This isn't the case with Indian vehicles. According to Varghese, the electronic control unit in an engine is hypersensitive to fuel content, which it detects automatically.

"If you put more ethanol in fuel, its chemical properties change, and therefore the engine management system has to be able to adapt, and older cars might not be able to do that," he said.

By way of solution, he said mechanics could quickly connect the unit to a computer and update the fuel composition setting.

However, one senior industry executive told *The Hindu* that vehicles that don't have electronic control units and injectors can't be made compatible with E20 as fuel. The executive said "about 95%" of all vehicles until the rollout of the BS-VI emission standards (in April 2020) were mechanically carbureted, meaning they didn't utilise any electronic units with sensors to regulate the delivery and treatment of fuel.

"When the blending happens, it alters the stoichiometric ratio, i.e., air-to-fuel ratio, which in turn affects the speed of combustion and heat release," Kuppili said. "Modern vehicles have sensors called electronic control units, which monitor the oxygen content and alter the amount of fuel and air needed."

With ethanol-blended petrol, he added, "you would need less air than usual, as ethanol has an oxygen atom. So this reduction can actually reduce pollutant emissions such as NOX, PM, and CO."

"The ethanol-blending policy itself is excellent. It has been successful in other parts of the world," Varghese said. "The ideas of energy security and saving import duty are excellent and true. It just needs to be paced better."

The principle of recalibration

The executive said the sensor's main purpose is to manage the spark timing – which determines the release pattern of the fuel and combustion inside the cylinder.

The electronic control unit uses the spark plug to create the spark that ignites the fuel-air blend in the combustion chamber. Older vehicles, i.e., those lacking the unit, have been tuned to a different fuel and are thus hard-coded for a different spark timing.

Since E20 brings more oxygen to the fuel-air mix, the executive explained, engines may have to be recalibrated by, among other measures, advancing the pressure for combustion and its eventual timing by two to three degrees. In other words, the engine will have to make sure combustion happens earlier so that there are no issues with starting the vehicle and with maintaining an adequate air-fill ratio across all load conditions and speeds.

This customisation isn't possible with mechanically carbureted vehicles.

The executive also affirmed that the adjustment would increase cost.

"You have to pay the calibration engineer and the vehicle component engineers," he said. The latter "charge good money."

(With inputs from Saptaparno Ghosh)

priyali.prakash@thehindu.co.in

समायोजित कर सकते हैं और E20 ईंधन के लिए बेहतर अनुकूलन कर सकते हैं।
- o पुराने वाहनों (2020 से पहले के कार्बोरेटेड इंजन) में पुनर्अंशांकन क्षमता का अभाव होता है → माइलेज में कमी, जंग लगने और अधिक रखरखाव की संभावना अधिक होती है।
- o सरकार का तर्क है कि कुछ रबर पुर्जों को बदलना सस्ता है, लेकिन उद्योग विशेषज्ञ पुराने वाहनों के लिए महंगे पुनर्अंशांकन पर प्रकाश डालते हैं।

4. पर्यावरणीय प्रभाव

- o इथेनॉल दहन में अतिरिक्त ऑक्सीजन लाता है → पार्टिकुलेट मैटर (PM), NOx और CO उत्सर्जन को कम करता है।
- o हालाँकि, जीवनचक्र उत्सर्जन उपयोग किए गए फीडस्टॉक पर निर्भर करता है। गन्ने के उपयोग से जल और भूमि उपयोग संबंधी चिंताएँ बढ़ सकती हैं।

तुलनाएँ और सबक

- ब्राज़ील का अनुभव: 1970 के दशक से मज़बूत शोध, सब्सिडी, फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों और उपभोक्ता तत्परता के साथ धीरे-धीरे बदलाव आया है।
- भारत की चुनौती: तेज़ रोलआउट, कम तैयारी, फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की पहुँच का अभाव, और इथेनॉल के लिए खाद्य फसलों पर अत्यधिक निर्भरता → गति और व्यावहारिकता को लेकर चिंताएँ पैदा करती है।

महत्वपूर्ण चिंताएँ

- ऊर्जा दक्षता: माइलेज में मामूली गिरावट संभव है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं (E10→E20)।
- वाहन सुरक्षा: पुराने वाहनों में जंग लगने और खराबी का ख़तरा ज़्यादा होता है।
- खाद्य सुरक्षा: इथेनॉल के लिए मक्का/चावल जैसे खाद्यान्नों का उपयोग खाद्य आपूर्ति पर दबाव डाल सकता है।
- आर्थिक लागत: पुनर्अंशांकन, घटकों का प्रतिस्थापन और सब्सिडी सरकार और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लागत बढ़ाती हैं।

निष्कर्ष

- भारत की इथेनॉल मिश्रण योजना ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ईंधन की दिशा में एक महत्वाकांक्षी प्रयास को दर्शाती है। विज्ञान बताता है कि माइलेज और दक्षता में नुकसान मामूली है, लेकिन ज़्यादा जोखिम जंग, वाहनों की असंगति और फीडस्टॉक के उपयोग की स्थिरता में हैं। ब्राज़ील से मिले सबक चरणबद्ध दृष्टिकोण, बुनियादी ढाँचे की तैयारी और वाहन अनुकूलन के महत्व को दर्शाते हैं। सफल होने के लिए, भारत को उपभोक्ता लागत, खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक तत्परता के साथ जलवायु लक्ष्यों को संतुलित करना होगा, तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि इथेनॉल कार्यक्रम विघटनकारी बोझ के बजाय हरित ऊर्जा परिवर्तन का एक स्थायी स्तंभ बन जाए।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इथेनॉल की ऑक्टेन संख्या पेट्रोल से अधिक होती है।

2. इथेनॉल का ऊष्मीय मान पेट्रोल से अधिक होता है।

3. इथेनॉल प्रकृति में आर्द्रताग्राही होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं**?**

(A) केवल **1** और **2**

(B) केवल **2** और **3**

(C) केवल **1** और **3**

(D) 1, 2 और **3**

उत्तर: C)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: इथेनॉल मिश्रण को जलवायु-अनुकूल नीति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह पर्यावरणीय स्थिरता**,** खाद्य सुरक्षा और आर्थिक लागत के लक्ष्यों को किस हद तक संतुलित करता है**? (150 Words)**

Page 08 :GS 2 : International Relations

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का शिखर सम्मेलन (15 अगस्त, 2025) ने रूस-यूक्रेन संघर्ष, अमेरिका-रूस संबंधों में सुधार और प्रमुख शक्तियों की भूमिका पर वैश्विक बहस को फिर से शुरू कर दिया है। हालाँकि, भारत के लिए इस बैठक ने अवसरों की तुलना में चिंताएँ अधिक पैदा की हैं। स्थिर अमेरिका-रूस संबंधों में भारत की हिस्सेदारी के बावजूद, शिखर सम्मेलन के परिणामों ने भारत की कूटनीतिक कमज़ोरी को कम करने में कोई खास मदद नहीं की – जो अपने दो सबसे करीबी लेकिन प्रतिस्पर्धी साझेदारों के बीच फँसा हुआ है।

Alaskan winds, India and the Trump-Putin summit

Suhasini Haidar

The "Alaska Moment" between United States President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin on August 15, 2025 will translate to other objectives for Ukraine as Mr. Trump engages with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and European leaders, leading up to a possible trilateral summit in a quest for the end of the Russia-Ukraine conflict. For New Delhi, however, the Alaska Summit did not yield the clear-cut outcomes many had hoped for before the meeting between the leaders of two of India's closest friends. Nor did it help the peculiar sense of vulnerability that Indian diplomacy faced, of having so much at stake in a meeting while having so little agency in its results.

Broadly, the Narendra Modi government had hoped that a U.S.-Russia rapprochement would take off some of the pressure from the U.S. India has felt over its ties with Russia. However, while there was a visible warmth in the Trump-Putin exchanges, this did not result in a less chilling tone that Mr. Trump has had towards India. He has been taking India to task on a number of issues.

More specifically, hopes rose that the Alaska meeting would result in a rollback of the U.S.'s planned 25% secondary sanctions on India for buying Russian oil; the resumption of India-U.S. trade talks that Mr. Trump has held up over the Russia oil issue; and a subsequent revision of the 25% reciprocal tariffs already in place. In a severely-worded piece in the *Financial Times* ("India's oil lobby is funding Putin's war machine – that has to stop"), Peter Navarro, who is Mr. Trump's Senior Counselor on Trade and Manufacturing, virtually dashed such hopes, making it clear that the double tariffs were a "two-pronged policy" by the U.S. to "hit India where it hurts", for both the Russian imports and for its curbs on market access.

No change in India policies

Nor was there any indicator that Mr. Trump would let up on the other pain point: his counter-narrative to the Modi government's account of Operation Sindoor (May 7-10) and how the ceasefire was achieved. Not only did Mr. Trump repeat that he has mediated the India-Pakistan ceasefire, using trade as a leverage to corral both sides, but he now adds that a nuclear conflict would have followed as both sides were "shooting down airplanes", a version at considerable odds from that of the Modi government, which has thus far conceded that it had no losses in the conflict.

Thus, the first takeaway from the Summit must be this: while Mr. Trump's re-engagement and bonhomie with Mr. Putin may help Moscow, it does not mean a revision of his policies toward India. In any case, the rationale behind the secondary sanctions on India is dubious, and more about power games than about punishing Russia. The U.S. has itself increased its trade with Russia since Mr. Trump came to power and China imports of Russian oil have been consistently larger than India's. Hitting India with sanctions while feting the Russian President and ignoring China's actions seems to indicate that the reasons for the U.S.'s actions lie elsewhere. Many have suggested that Mr. Trump has acted out of pique – upset that Mr. Modi ignored his claims to have mediated with the Pakistanis. Reports suggested that Mr. Modi also rebuffed U.S. moves for him to sit down with the Pakistani leadership in Riyadh or in Washington, and that the Modi-Trump call on June 17 was extremely acrimonious and awkward as a result. Mr. Trump's more obvious focus appears to be recognition for his peace-making efforts, and a possible Nobel Peace Prize, and the Modi government has already missed the bus to give him the credit for the Operation Sindoor ceasefire that Mr. Trump so clearly wants.

> The visible warmth in the Trump-Putin exchanges did not result in a less chilling American tone towards India; the lesson for New Delhi is that it would need to take a firmer stance if it wants to get back its agency

New Delhi must decide whether it wishes to jump through hoops for Washington, or whether it would be more sensible to step back and allow the Trump administration to do its worst before assessing a response and turn its energies to other parts of the world. There may be avenues to shore up India's options on trade relationships with Mr. Modi's upcoming visits to Japan and then to China for the Shanghai Cooperation Organisation meet, a possible visit to the U.S. for the United Nations General Assembly, and then South Africa for the G-20 summit. There is also Mr. Putin's visit to India soon. The bellwether event for India-U.S. ties will be the upcoming Quad Summit (India, U.S., Japan, Australia) that India is due to host later this year. It is still unclear whether Mr. Trump will visit India, especially if no India-U.S. trade deal is done by then, and whether the Indian government will be in any mood to roll out the red carpet.

Returning to substance

The second takeaway should be a lesson in not allowing "Summitry" to overtake India's broader interests. For more than a decade, the "Modi mantra" of foreign policy has been about personal magic and chemistry, of dealing one-to-one with leaders of other countries, as his imprimatur on bilateral ties. As a result, visits abroad have been judged by the number of joint public appearances, handshakes and embraces as well as special honours and awards that are given to the Prime Minister, rather than the actual agreements and concessions between them. With China, however, the 18 one-on-one meetings between Mr. Modi and China's President Xi Jinping between 2014-19 did not generate the requisite understanding to foresee Chinese People's Liberation Army's transgressions along the Line of Actual Control and the Galwan clashes.

With the U.S., too, Mr. Modi's close engagements during the Trump 1.0 tenure (the 'Howdy Modi' rally in Texas in 2019 and the 'Namaste Trump' rally in Gujarat in 2020), as well as his early visit to Washington under the Trump 2.0 administration in February 2025 should have given the two leaders enough of an understanding of the other. Given the shocks that have followed, it may be time to turn back the focus to substance over style. But that substance becomes more difficult to seek in Trumpian times, given that most foreign policy decisions are being taken by Mr. Trump himself and a small ring around him in the White House, with few appointments being made on the desks that deal with India in the National Security Council or the State Department. In the 'good times' Delhi and Washington have worked well, even without a U.S. Ambassador in place in India. But at present, it is clear that a senior envoy with a keen knowledge of India as well as the U.S. President's ear are necessary to navigate the turbulence in ties.

Maintain a political balance

The third lesson of the past few months is that India must reclaim bipartisanship in diplomatic relations, and build and maintain ties on both sides of the political spectrum, regardless of which party is in power. In the U.S., the Democratic party establishment was unhappy about the Trump-Modi rallies because they were held just months before the U.S. presidential election in 2020, and India had to spend some time, subsequently, repairing ties with the Joe Biden administration. Four years later, this annoyed Mr. Trump, the Republican contender, especially as he felt the contrast between the close personal bonhomie while he was in power and the fact that the Mr. Modi and his envoys did not spend time with him when he was out of power, including during the three times Mr. Modi travelled to the U.S., in 2021, 2023 and 2024, to hold talks with Mr. Biden. Closer home, this bipartisanship has been proven to trip up India's ties in the neighbouring countries as well – Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and the Maldives.

Fourth, Mr. Trump's penalties on India's import of oil, after the U.S. allowed, even actively encouraged the purchases before, show how fickle the global power can be and how futile it is for India to forego its principles in order to please a particular regime. India's time-honoured principle of only acceding to UN-mandated sanctions was broken in 2018 when the government bowed to Mr. Trump's threats of sanctions against Iranian oil, and then Venezuelan oil, possibly emboldening him to demand the same against the use of Russian oil this time. By accepting such unreasonable orders, India does not just risk economic losses in foregoing cheaper oil. It also becomes complicit in the U.S.'s foreign policy objectives that do not necessarily align with India's national interests. Conversely, when India resists such moves, it wins the support of others in the Global South. And while they object, western powers grudgingly accept India's strategic autonomy in these matters.

Finally, New Delhi must consider measures and countermeasures to deal with U.S. actions that hurt India's interests acutely – like the reciprocal and penalty tariffs that will make Indian goods far less competitive than those of its exporting rivals, curbs on U.S. manufacturing in India, or the remittance taxes on Indians working in the U.S. Getting back India's agency will require a firmer stance – one that is not buffeted by the winds in Alaska, at a summit meeting thousands of kilometres away from India.

suhasini.h@thehindu.co.in

भारत की अपेक्षाएँ बनाम परिणाम

1. ऊर्जा और प्रतिबंध

- o भारत को रूसी तेल खरीदने पर लगाए गए द्वितीयक अमेरिकी प्रतिबंधों (25%) से राहत की उम्मीद थी।
- o इसके बजाय, अमेरिकी बयानों ने प्रतिबंधों को और मज़बूत कर दिया, उन्हें भारत द्वारा "पुतिन की युद्ध मशीन को वित्तपोषित" करने से जोड़ा।
- o दोहरे टैरिफ (पारस्परिक 25%) बरकरार हैं, जिससे भारतीय व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुँच रहा है।

2. व्यापार और बाज़ार पहुँच

- o रुके हुए भारत-अमेरिका संबंधों पर कोई प्रगति नहीं हुई। व्यापार वार्ता अभी भी रूस के तेल मुद्दे के कारण अटकी हुई है।

3. ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) पर कहानी

- o ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से भारत-पाकिस्तान युद्धविराम में मध्यस्थता का श्रेय लिया, जो नई दिल्ली के सफलता के आख्यान का खंडन करता है।
- o इससे तनाव पैदा हुआ है और भारत की कूटनीतिक स्थिति को नुकसान पहुँचा है।

4. भू-राजनीतिक संकेत

- o जहाँ अमेरिका-रूस की गर्मजोशी मास्को के लिए फायदेमंद है, वहीं भारत को वाशिंगटन से लगातार दबाव और संदेह का सामना करना पड़ा।
- o चीन द्वारा रूसी तेल के बड़े आयात को अमेरिका ने नज़रअंदाज़ कर दिया, जिससे पता चलता है कि भारत को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया गया था।

भारत के लिए मुख्य सबक

1. शिखर सम्मेलन कूटनीति पर अत्यधिक निर्भरता से बचें

- o मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति ("शिखर सम्मेलन" और नेता केमिस्ट्री) ने अक्सर सार की बजाय शैली को प्राथमिकता दी है।
- o उदाहरण: 18 मोदी-शी बैठकों (2014-2019) के बावजूद, भारत गलवान से अचंभित था।

2. द्विदलीयता पुनः प्राप्त करें

- o "हाउडी मोदी" और "नमस्ते ट्रम्प" रैलियों में भारत की भागीदारी ने भारत को अमेरिकी घरेलू राजनीति से बहुत अधिक जोड़ दिया।
- o दीर्घकालिक कूटनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए द्विदलीय संबंध आवश्यक हैं।

3. रणनीतिक स्वायत्तता पर कायम रहें

- o ईरान और वेनेजुएला (2018) पर अमेरिकी प्रतिबंधों के आगे झुककर, भारत ने अपने सिद्धांतों से समझौता किया और वाशिंगटन को प्रोत्साहित किया।
- o ऊर्जा विकल्पों में रणनीतिक स्वायत्तता वैश्विक दक्षिण में विश्वसनीयता बढ़ाती है।

4. प्रतिवाद तैयार करें

- o भारत को दंडात्मक शुल्कों, व्यापार प्रतिबंधों और प्रेषण करों की भरपाई के विकल्प तलाशने चाहिए।
- o जापान, चीन (एससीओ), रूस और जी-20 भागीदारों के साथ साझेदारी में विविधता लाने से अमेरिकी दबाव कम हो सकता है।

निष्कर्ष

- अलास्का शिखर सम्मेलन दर्शाता है कि जब महाशक्तियों के बीच सौदे होते हैं, तो वैश्विक भू-राजनीति में भारत की भूमिका कैसे सीमित रहती है। भारत के लिए, आगे बढ़ने का रास्ता एक शक्ति की सनक पर निर्भरता कम करने, प्रतिबंधों और ऊर्जा सुरक्षा पर अपने सैद्धांतिक रुख को मज़बूत करने और विभिन्न गुटों के बीच संबंधों को पुनर्संतुलित करने में निहित है। व्यक्तित्व-आधारित शिखर सम्मेलनों से हटकर ठोस, संस्थागत और बहु-स्तरीय कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करके, भारत बदलती वैश्विक हवाओं के बीच अपनी रणनीतिक स्थिति को सुरक्षित रख सकता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: 2025 के ट्रम्प-पुतिन अलास्का शिखर सम्मेलन ने भारत की बिना एजेंसी के दांव लगाने की कमज़ोरी को उजागर कर दिया। इस संदर्भ में**,** चर्चा कीजिए कि भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंधों को संभालते हुए अपनी सामरिक स्वायत्तता को कैसे मज़बूत कर सकता है। **(150 Words)**

Page 09 :GS 1 : Indian Society

भारत में महिला सशक्तिकरण का जश्न अक्सर प्रतीकात्मक संकेतों - पुरस्कारों, मीडिया में प्रतिनिधित्व और सफल नेताओं की मान्यता - के माध्यम से मनाया जाता है। हालाँकि, सच्चा सशक्तिकरण आम महिलाओं, खासकर हाशिए की पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बर्बादी या व्यवस्थागत उपेक्षा के डर के बिना, जड़ जमाए सत्ता संरचनाओं के खिलाफ खड़ा होने में सक्षम बनाने में निहित है। एक शक्तिशाली राजनेता के खिलाफ कानूनी लड़ाई में डटी रहने वाली एक घरेलू सहायिका का मामला, महिला सशक्तिकरण पर भारत के विमर्श में बयानबाजी और वास्तविकता के बीच के अंतर को उजागर करता है।

What true empowerment of women entails

Apsara Reddy

AIADMK Spokesperson

The trial of former Janata Dal (Secular) MP Prajwal Revanna, tainted by every trick in the book that power can muster, from legal intimidation to procedural delays, could have been yet another grim entry in India's long and exhausting history of justice denied. However, this case was different because a 47-year-old domestic help, with no wealth, no political connections, and no media machinery at her disposal, refused to be worn down. She braved high-profile legal muscle, relentless attempts at discrediting her, and the quiet but crushing social pressures that compel victims to disappear into silence. She didn't disappear; instead, she stood her ground.

The language of empowerment

India loves the language of empowerment. We put women entrepreneurs on magazine covers, we host conferences celebrating women CEOs, and we create awards to honour women leaders in politics, business, and culture. Yet, when a woman without privilege takes on the powerful in a court of law, we often treat her as a passing headline; not as a hero whose actions have fortified the very concept of justice. Our narrative of empowerment too often belongs to those who have the resources to recover from failure, the networks to cushion backlash, and the privilege to choose their battles. We rarely extend the same recognition and support to women whose fight is not for market share or boardroom representation, but for their very survival. Women like this domestic help are not just defending their rights; they are performing a form of public service. Their win strengthens the jurisprudence for every woman who will walk into a police station trembling, unsure if she will be heard.

And yet, the moment the verdict is read, the applause dies down and the state, which was happy to bask in the optics of justice served, does little to ensure that these women can rebuild their lives. The women return to the same environment where abuse took place, facing retaliatory stigma, finding themselves jobless because it is "too much trouble" to employ someone who has been in court, or sinking under the weight of legal debts incurred during the fight. If governments, corporates, and civil society are serious about "women empowerment", they must provide these women structural support – legal, economic, and psychosocial – to ensure that victory in court does not translate into defeat in life.

The way forward

We need state-funded survivor compensation schemes. Frameworks exist to provide financial compensation to families of crime victims in categories such as terrorism or industrial accidents, so why should a woman who has stood up against entrenched power, faced character assassination, and endured court battles not receive similar recognition and financial security? The compensation should be calculated not only to cover legal expenses but to secure a minimum period of stability.

We need dedicated legal aid cells with special funding. Most women in such cases are bankrupted by the legal process. While legal aid exists in theory, it is woefully under-resourced and often inaccessible. States must create specialised survivor litigation cells with professional advocates, forensic experts, and victim support officers, funded on par with public prosecutors in high-profile cases.

We need guaranteed employment pathways. Governments, public sector undertakings, and corporates should create direct employment quotas for survivors of legal battles against abuse and harassment.

We need psychological support and trauma recovery. Survivors require structured access to long-term counselling, peer support networks, and therapy sessions, funded by the state and supplemented by CSR initiatives. Trauma recovery must be treated as a right, not as a luxury.

Most importantly, we must institutionalise survivor expertise. Women who have navigated intimidation, isolation, and legal complexity should be trained and appointed as counsellors for victims in police stations to guide them through the first and often most critical reporting stage; as mentors in community legal education programmes to demystify the justice process for other women; and as members of Internal Complaints Committees under POSH laws, where their lived experience can lend authenticity and empathy to workplace grievance redressal. This will not only provide survivors with income, but ensure that their courage is institutionalised, not forgotten.

One might ask, why we should single out women like this? Why not simply improve the justice system for all? The answer is simple: they are fighting battles that, in the absence of systemic reform, remain exceptions. Supporting them visibly and meaningfully sends a signal to both potential victims and potential abusers that the state does not abandon those who resist, and that the cost of silencing them will only rise. Moreover, recognising these women's courage in concrete, life-changing ways reshapes our national idea of empowerment.

Applause is easy; it costs nothing. But when a woman risks everything to hold a powerful man accountable, society owes her more than praise; it owes her a future. That future must be secured through a combination of immediate economic support, long-term professional integration, and the legitimisation of survivor voices in policymaking and institutional culture. Only then can we say that empowerment has been delivered, not just declared.

> Women who fight for justice deserve more than applause; they deserve a future

उजागर किए गए मुख्य मुद्दे

1. सशक्तिकरण के सतही आख्यान

- आमतौर पर नेतृत्व की भूमिकाओं में विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं पर केंद्रित होता है।
- दुर्व्यवहार या उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के जमीनी संघर्षों को बहुत कम मान्यता मिलती है।

2. पीड़ितों के लिए व्यवस्थागत चुनौतियाँ

- कानूनी जीत के बाद, पीड़ितों को अक्सर नौकरी छूटने, कलंक और आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।
- कानूनी खर्च और सामाजिक अलगाव आघात को और बढ़ा देते हैं, जिससे न्याय एक खोखली जीत बन जाता है।

3. राज्य और संस्थागत कमियाँ

- मौजूदा कानूनी सहायता अभी भी दुर्गम और अपर्याप्त वित्तपोषित है।
- अन्य पीड़ितों (आतंकवाद, औद्योगिक दुर्घटनाएँ) के लिए उपलब्ध योजनाओं की तुलना में उत्तरजीवी पुनर्वास ढाँचे कमज़ोर हैं।

आगे की राह

1. राज्य द्वारा वित्तपोषित उत्तरजीवी मुआवज़ा योजनाएँ - कानूनी खर्चों को कवर करने और मुकदमे के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए।
2. समर्पित कानूनी सहायता प्रकोष्ठ - पेशेवर अधिवक्ताओं और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ उत्तरजीवी मुकदमेबाजी में विशेष सहायता।
3. रोज़गार के सुनिश्चित रास्ते - उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के मामलों के उत्तरजीवियों के लिए सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कोटा।
4. मनोवैज्ञानिक सहायता और आघात से उबरना - राज्य और सीएसआर पहलों द्वारा वित्तपोषित परामर्श और चिकित्सा तक संरचित पहुँच।
5. उत्तरजीवी विशेषज्ञता का संस्थागतकरण - सहानुभूति-आधारित शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरजीवियों को POSH के तहत परामर्शदाता, संरक्षक और समिति सदस्य के रूप में नियुक्त करना।

आलोचनात्मक विश्लेषण

- लेख प्रतीकात्मक सशक्तिकरण और वास्तविक सशक्तिकरण के बीच अंतर को रेखांकित करता है।
- सशक्तिकरण को दिखावे से आगे बढ़कर परिणामों की ओर बढ़ना होगा - कानूनी जीत आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति और संस्थागत एकीकरण में तब्दील होनी चाहिए।
- पीड़ित-केंद्रित नीतियाँ न केवल न्याय को मज़बूत करेंगी, बल्कि संस्थाओं में जनता का विश्वास भी बढ़ाएँगी।
- हालाँकि, ऐसे उपायों को न्याय प्रणाली में व्यापक प्रणालीगत सुधारों के पूरक के रूप में सभी पीड़ितों के लिए, चाहे उनका लिंग या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समानता सुनिश्चित करनी चाहिए।

निष्कर्ष

- सच्चा महिला सशक्तिकरण बोर्डरूम, पुरस्कारों या औपचारिक समारोहों तक सीमित नहीं हो सकता। इसे सबसे कमज़ोर आवाज़ों - विशेषाधिकार, संसाधन या नेटवर्क से वंचित महिलाओं - को सशक्त बनाना होगा, जो जड़ जमाए सत्ता संरचनाओं को चुनौती देती हैं। कानूनी, वित्तीय, मनोवैज्ञानिक और पेशेवर ढाँचों के माध्यम से पीड़ित समर्थन को संस्थागत बनाकर, समाज यह सुनिश्चित कर सकता है कि न्याय केवल अदालतों में ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मिले। असली सशक्तिकरण तालियों में नहीं, बल्कि अन्याय का विरोध करने का साहस करने वाली हर महिला के लिए सम्मान, आजीविका और सुरक्षा सुनिश्चित करने में निहित है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: वाहवाही बटोरना आसान है; सशक्तिकरण के लिए व्यवस्थित समर्थन की आवश्यकता होती है। इस कथन के आलोक में, भारत में कानूनी जीत हासिल करने के बाद भी दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक उपाय सुझाइए। **(150 Words)**

Page : 08 Editorial Analysis

The path to ending global hunger runs through India

With global chronic undernourishment now on a downward trend, the world is beginning to turn a corner in its fight against hunger. The United Nations' newly released The State of Food Security and Nutrition in the World 2025 reports that 673 million people (8.2% of the world's population) were undernourished in 2024. This is down from 688 million in 2023. Although we have not yet returned to pre-pandemic levels (7.3% in 2018), this reversal marks a welcome shift from the sharp rise experienced during COVID-19.

India has played a decisive role in this global progress. The gains are the result of policy investments in food security and nutrition, increasingly driven by digital technology, smarter governance, and improved service delivery.

Revised estimates using the latest National Sample Survey data on household consumption show that the prevalence of undernourishment in India declined from 14.3% in 2020-22 to 12% in 2022-24. In absolute terms, this means 30 million fewer people living with hunger – an impressive achievement considering the scale of the population and the depth of disruption caused by the COVID-19 pandemic.

Maximo Torero Cullen

is Chief Economist, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

The transformation of the PDS

At the centre of this progress is India's Public Distribution System, which has undergone a profound transformation. The system has been revitalised through digitalisation, Aadhaar-enabled targeting, real-time inventory tracking, and biometric authentication. The rollout of electronic point-of-sale systems and the One Nation One Ration Card platform have made entitlements portable across the country, which is particularly crucial for internal migrants and vulnerable households.

> India's decisive role in the the world's fight against hunger is a result of its policy investments in food security and nutrition

These innovations allowed India to rapidly scale up food support during the pandemic and to continue to ensure access to subsidised staples for more than 800 million people.

Now, progress on calories must give way to progress on nutrition. The cost of a healthy diet in India remains unaffordable for over 60% of the population, driven by high prices of nutrient-dense foods, inadequate cold chains, and inefficient market linkages. That said, India has begun investing in improving the quality of calories. For example, the Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN) school-feeding scheme, launched in 2021, and the Integrated Child Development Services are now focusing on dietary diversity and nutrition sensitivity, laying the foundation for long-term improvements in child development and public health.

New data in the UN report also shows progress the country has made in making healthy diets more affordable despite food inflation.

What is happening underscores a larger structural challenge: even as hunger falls, malnutrition, obesity, and micronutrient deficiencies are rising. This is especially so among poor urban and rural populations.

The agrifood system needs transformation

India can meet this challenge by transforming its agrifood system. This means boosting the production and the affordability of nutrient-rich foods such as pulses, fruits, vegetables, and animal-source products, which are often out of reach for low-income families. It also means investing in post-harvest infrastructure such as cold storage and digital logistics systems, to reduce the estimated 13% of food lost between farm and market. These losses directly affect food availability and affordability.

In addition, India should further strengthen support for women-led food enterprises and local cooperatives, including Farmer Producer Organizations (FPOs), especially those cultivating climate-resilient crops, as these can enhance both nutrition and livelihoods.

India must continue to invest in its digital advantage to drive the transformation of its agrifood systems. Platforms such as AgriStack, e-NAM, and geospatial data tools can strengthen market access, improve agricultural planning, and enhance the delivery of nutrition-sensitive interventions.

A symbol of hope

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) notes that the progress of India in agrifood system transformation is not just national imperatives; they are global contributions. As a leader among developing countries, India is well-positioned to share its innovations in digital governance, social protection, and data-driven agriculture with others across the Global South. India's experience shows that reducing hunger is not only possible but that it can be scaled when backed by political will, smart investment, and inclusion.

With just five years left to meet the Sustainable Development Goals (SDG), including SDG 2 (Zero Hunger) on ending hunger, India's recent performance gives this writer hope. But sustaining this momentum will require a shift from delivering sustenance to delivering nutrition, resilience, and opportunity.

The hunger clock is ticking. India is no longer just feeding itself. The path to ending global hunger runs through India, and its continued leadership is essential to getting us there.

GS. Paper 02 अंतरराष्ट्रीय संबंध

UPSC Mains Practice Question: वैश्विक भुखमरी को समाप्त करने का मार्ग भारत से होकर गुजरता है।" वैश्विक स्तर पर भुखमरी और कुपोषण को कम करने में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तथा एसडीजी-2 (भूखमरी को समाप्त करने) के लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। (150 words)

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र एफएओ की नवीनतम रिपोर्ट (एसओएफआई 2025) से पता चलता है कि वैश्विक कुपोषण 2024 में घटकर 8.2% (673 मिलियन लोग) रह जाएगा, जो महामारी से प्रेरित वृद्धि को उलट देगा। इस प्रगति का एक प्रमुख कारण भारत में खाद्य सुरक्षा में सुधार है, जहाँ कुपोषण 14.3% (2020-22) से घटकर 12% (2022-24) हो गया है - जिससे 30 मिलियन लोग भूख से मुक्त हुए हैं। इस सफलता का श्रेय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), डिजिटल शासन और पोषण-केंद्रित योजनाओं में सुधारों को दिया जाता है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. पीडीएस का पुनरोद्धार

- आधार-सक्षम लक्ष्यीकरण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ई-पीओएस और रीयल-टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग।
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ने पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की, जिससे प्रवासियों को लाभ हुआ।
- महामारी के दौरान 800 मिलियन से अधिक लाभार्थियों तक पहुँच बनाई गई।

2. पोषण-उन्मुख योजनाएँ

- पीएम पोषण (2021) और आईसीडीएस आहार विविधता पर केंद्रित हैं।
- खाद्य मुद्रास्फीति के बावजूद स्वस्थ आहार की बढ़ती सामर्थ्य।

3. डिजिटल और शासन नवाचार

- एग्रीस्टैक, ई-नाम जैसे प्लेटफ़ॉर्म और बाज़ार पहुँच, योजना और वितरण के लिए भू-स्थानिक उपकरण।
- कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए भारत के डिजिटल लाभ का लाभ उठाना।

उभरती चुनौतियाँ

1. पोषण बनाम कैलोरी

- हालाँकि भूख कम हुई है, 60% से ज़्यादा भारतीय स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकते।
- दालों, फलों, सब्जियों और पशु उत्पादों की ऊँची कीमतें।

2. कुपोषण का तिहरा बोझ

- कुपोषण, मोटापा और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, खासकर गरीब परिवारों में, एक साथ मौजूद हैं।

3. खाद्य प्रणाली की अक्षमताएँ

o कमज़ोर भंडारण और रसद के कारण कटाई के बाद लगभग 13% खाद्यान्न हानि।

o अपर्याप्त कोल्ड चेन और खंडित बाज़ार।

आगे की राह

1. कृषि-खाद्य प्रणाली में परिवर्तन

o पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और सामर्थ्य को बढ़ावा देना।

o कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल खाद्य आपूर्ति प्रणालियों में निवेश करना।

2. महिलाओं और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को समर्थन देना।

o जलवायु-अनुकूल फसलों, सहकारी मॉडलों और महिलाओं के नेतृत्व वाले खाद्य उद्यमों को प्रोत्साहित करना।

3. कैलोरी से पोषण तक

o योजनाओं में आहार विविधता का विस्तार करना।

o दालों, बाजरा और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना।

4. वैश्विक नेतृत्व

o डिजिटल शासन और खाद्य सुरक्षा नवाचारों में भारत के अनुभव को वैश्विक दक्षिण के साथ साझा करना।

o 2030 तक एसडीजी-2 (भूख से मुक्ति) के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना।

आलोचनात्मक विश्लेषण

- भारत खाद्य-घाटे वाले देश से खाद्य सुरक्षा में एक वैश्विक अग्रणी देश बन गया है।
- डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की सफलता विकासशील देशों के लिए एक आदर्श है।
- हालाँकि, पोषण संबंधी चुनौतियों (अंतर्निहित भूख, मोटापा) के लिए व्यवस्थित कृषि-खाद्य सुधारों की आवश्यकता है।
- घरेलू प्रगति और नीतिगत नवाचारों के निर्यात, दोनों के माध्यम से, भूख के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई को आकार देने में भारत का नेतृत्व केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

निष्कर्ष

- भारत की प्रगति दर्शाती है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, डिजिटल नवाचार और लक्षित सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से बड़े पैमाने पर भूख में कमी लाना संभव है। फिर भी, अगला कदम "लोगों को भोजन" देने से "लोगों का पोषण" करने की ओर बढ़ना है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए पाँच वर्ष शेष होने के साथ, यह लेख इस बात पर ज़ोर देता है कि शून्य भुखमरी का वैश्विक मार्ग भारत से होकर गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए इसका निरंतर नेतृत्व महत्वपूर्ण हो जाता है।